कामये दुरवतमानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

वर्ष:64 | अंक- 2 | मुम्बई | जनवरी 2020

नगरोटा की आतंकवाद प्रभावित महिलाओं द्वारा बनाये गए खादी रुमाल की बिक्री का एमएसएमई मंत्री द्वारा शुभारम्भ

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष 64 अंक–2 मुंबई जनवरी 2020

सम्पादकीय मण्डल

अध्यक्ष
श्रीमती प्रीता वर्मा

संपादक
एम. राजन बाबू

उप संपादक
सुबोध कुमार

वरिष्ठ हिंदी अनुवाद अधिकारी
सरस्वती खनका

डिजाईन व पृष्ठसज्जा
सुबोध कुमार

प्रचार, फ़िल्म एवं लोक शिक्षण
कार्यक्रम निदेशालय द्वारा
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई -400056
के लिए ई-प्रकाशित
ईमेल: kvicpub@gmail.com
वेबसाइट: www.kvic.org.in

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा संपादक सहमत हों

इस अंक में

समाचार सार ..... 3 से 16

आयोग अपने वास्तविक अर्थों में बापू के सपने को साकार कर रहा है: आजीविका को पुनर्परिभाषित करते हुए, लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा में 500 बी बॉक्स, 500 कुम्हारी चाक और 200 लेदर टूल किट वितरित किए.....

नगरोटा की आतंकवाद प्रभावित महिलाओं द्वारा बनाये गए खादी रुमाल की बिक्री का एमएसएमई मंत्री द्वारा शुभारम्भ.....

त्रिपुरा में आजीविका पुनर्जीवित करती खादी: मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब द्वारा अगरतला में 1000 मधुमक्खी बॉक्स, 100 विद्युत चालित कुम्हारी चाक और लेदर टूल किट वितरित.....

आयोग ने पेपरेक्स-2019 में भाग लिया.....

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना, चेन्नई में 28 दिसंबर, 2019 को खोले गए तीसरे खादी फ्रेंचाइज आउटलेट का उद्घाटन.....

केवीआईसी पेंशनरों के लिए पेंशन भुगतान प्रणाली को मजबूत करने हेतु आयोग और भारतीय स्टेट बैंक, सीपीपीसी की बैठक.....

आयोग द्वारा महिलाओं को विद्युत चालित कुम्हारी चाक वितरित.....

आयोग ने डा. बी. आर. अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि.....

विविध.....

27 दिसंबर को हनी मिशन कार्यक्रम के तहत नासिक जिले में मधुमक्खी बक्सों का वितरण.....

प्रेस कवरेज .....17 से 21

आयोग अपने वास्तविक अर्थों में बापू के सपने को साकार कर रहा है

आजीविका को पुनर्परिभाषित करते हुए, लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा में 500 बी बॉक्स, 500 कुम्हारी चाक और 200 लेदर टूल किट वितरित किए

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाने के लिए और समाज के कमजोर वर्ग को सहयोग करने के लिए राजस्थान के बूंदी जिले में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 8 दिसंबर, 2019 को एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना और विधायक श्री अशोक डोगरा की उपस्थिति में 500 बी बॉक्स, 500 विद्युत चालित कुम्हारी चाक और 200 लेदर टूल किट वितरित किए गये, जिससे इस क्षेत्र में 50 मधुमक्खी पालकों, 2000 कुम्हारों और 200 चर्म कारीगरों की आजीविका का सृजन हुआ।

उल्लेखनीय रूप से, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हनी मिशन, कुम्हार सशक्तिकरण मिशन और चर्म मिशन के तहत पिछले 2-3 वर्षों से मधुमक्खी पालन उद्योग, कुम्हारी उद्योग और चर्म उद्योग के पुनरुद्धार के लिए एक बड़े अभियान का नेतृत्व किया है। आयोग ने अब तक देश भर में लगभग 1.7 लाख मधुमक्खी के बक्से, 13000 विद्युत चालित कुम्हारी चाक, 1500 लेदर किट वितरित किए हैं, इस प्रकार अब तक 17,000 मधुमक्खी पालनकर्ताओं, 52,000 कुम्हारों और 1500 चमड़ा कारीगरों के लिए आजीविका का सृजन किया गया है।

केवीआईसी के प्रयासों को लागू करते हुए, श्री ओम बिरला ने कहा, "बापू ने हमेशा ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और उनके घर पर आजीविका के अवसर प्रदान करने का सपना देखा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने वास्तविक

अर्थों में बापू के सपने को पूरा कर रहा है। मधुमक्खी पालन, कुम्हारी और चमड़ा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए केवीआईसी की पहल काफी हद तक सफल होगी, जिससे ग्रामीण युवाओं को अपना सम्मान हासिल करने में मदद मिलेगी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा, "इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाना और मधुमक्खी पालन, कुम्हारी और चर्म व्यवसाय की कलात्मकता में विश्वास हासिल करने में उनकी मदद करना है। प्रधान मंत्री के विजन से संकलित, हमारा प्रयास आजीविका के अवसरों के साथ-साथ ग्रामीण किसानों को आय का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना है जो अन्यथा वैकल्पिक श्रम को अपनाते हैं या दैनिक मजदूरी की नौकरियों के लिए बड़े शहरों या शहरों में पलायन करते हैं।

"उत्तर-पश्चिम रेलवे ने हाल ही में इसी सन्दर्भ में, अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर में तैनात वरिष्ठ जोनल वाणिज्य प्रबंधकों को 25 विभिन्न रेलवे स्टेशनों में खानपान की वस्तुओं की सेवा के लिए टेराकोटा से बने कुल्हड़, गिलास और प्लेट्स की आपूर्ति करने के लिए एक निर्देश जारी किया था।

तत्काल प्रभाव से राजस्थान में उपलब्ध तैयार बाजार पर टिप्पणी करते हुए, श्री सक्सेना ने आगे कहा, "केवीआईसी आज भारतीय ग्रामोद्योग को फिर से परिभाषित कर रहा है। जहां एक ओर यह जागरूकता फैला रहा है और आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का वितरण कर रहा है, वहीं उन्नत प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है, दूसरी ओर यह सरकार के साथ लाभार्थियों के द्वार पर विपणन सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।

इस कार्यक्रम में राजस्थान के झालावाड, कोटा और बूंदी जिलों के उत्साहित कारीगरों की भारी भीड़ देखी गई। एक लाभार्थी कुम्हार पप्पू प्रजापति ने कहा, "हम अपने गाँव में विद्युत चालित कुम्हारी चाक वितरित करने के लिए दिल्ली से आने के लिए श्री ओम बिरला जी और श्री वी.के. सक्सेना जी के बहुत आभारी हैं। नए कुम्हारी चाक से शारीरिक श्रम कम होगा और यह उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करेगा, जबकि व्यक्ति के प्रति घन्टे कार्य को काफी कम कर देता है। हम विद्युत चालित कुम्हारी चाक की मदद से पहले की तुलना में लगभग दोगुनी आय उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। ऐसा ही, हमारे गाँव के सभी मधुमक्खी पालकों और चर्म कारीगरों को सहयोग करना चाहिए। हम केवीआईसी द्वारा दिए गए इस नए साल के तोहफे के लिए धन्यवाद देते हैं।"

नगरोटा की आतंकवाद प्रभावित महिलाओं द्वारा बनाये गए

खादी रुमाल की बिक्री का एमएसएमई मंत्री द्वारा शुभारम्भ

नई दिल्ली, 16 दिसंबर: माननीय केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने श्री शांगरी ला के एरोस में नगरोटा की आतंकवाद प्रभावित महिलाओं द्वारा बनाये गए खादी रुमाल की बिक्री का शुभारंभ किया, इस अवसर पर माननीय एमएसएमई राज्य मंत्री श्री प्रताप चन्द्र सारंगी और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना भी उपस्थिति थे।

कुछ साल पहले, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए, कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों के परिवार जम्मू के एक छोटे से शहर नगरोटा में स्थानांतरित हो गए। 2016 में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आजीविका और रोजगार के अवसरों की कमी से प्रभावित महिलाओं के लिए नगरोटा में एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जिससे उन्हें आत्म-निर्भर बनने और अपने परिवारों को बनाए रखने में मदद मिल सके।

इस पहल के बारे में बोलते हुए, श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा, "यह 'खादी रुमाल' केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि नगरोटा में रहने वाली आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं को भारत के लोगों ने उन्हें सक्षम बनाने और उन्हें सम्मान और सम्मान की जिंदगी जीने के लिए सशक्त बनाया है। इस खादी रुमाल की बिक्री आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और पूरे कश्मीर की महिलाओं को बाहर निकलने और खुद के लिए खड़े होने, एक सम्मानजनक आजीविका कमाने और अपने परिवारों की देखभाल करने में सक्षम बनाएगी। यह भारत के लिए एकजुट होने और लोगों की मदद करने का समय है।

"शुद्ध खादी से बना यह सफेद खादी रुमाल भारत में 8000 से अधिक खादी दुकानों में 1, 3 और 5 के पैक में बेची जाएगा। ऑनलाइन बिक्री को सक्षम करने के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इसकी उपलब्धता बढ़ाने के लिए पेटीएम जैसे ईकॉमर्स पोर्टल के साथ भी करार किया है।

श्री सक्सेना ने आगे कहा, "हमने शुरू में 5 करोड़ खादी रुमाल बेचने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, यह 'परिवर्तन यात्रा' की शुरुआत है। 'यह एक ऐसा अवसर है जहां नगरोटा की महिला कारीगरों को सशक्त बनाने और कश्मीर की उन सभी महिलाओं को भी, जो अभी भी लाइन में हैं और परिवर्तन की इस यात्रा में शामिल होने के लिए तत्पर हैं - उन्हे आत्मनिर्भर बनाने में हर भारतीय नागरिक राष्ट्र निर्माण का एक हिस्सा हो सकता है।"

त्रिपुरा में आजीविका पुनर्जीवित करती खादी

मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब द्वारा अगरतला में 1000 मधुमक्खी बॉक्स, 100 विद्युत चालित कुम्हारी चाक और लेदर टूल किट वितरित

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जिसने हनी मिशन, कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम और चर्म कारीगरों के सशक्तीकरण जैसे अपने आजीविका सृजन कार्यक्रमों की मदद से भारत के दूरस्थ भागों में अपनी उपस्थिति को मजबूत की है, इसी क्रम में आयोग ने 23 दिसंबर 2019 को उत्तर-पूर्व के दूसरे सबसे बड़े शहर, अगरतला में एक विशाल उपकरण वितरण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया।

महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाने और अगरतला में समाज के कमजोर वर्ग के सहयोग के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 1000 बी बॉक्स, 100 विद्युत चालित कुम्हारी चाक और 100 एडवांस्ड लेदर टूल किट क्रमशः 100 किसानों, 100 किसानों और 100 लेदर कारीगरों को वितरित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजन किया गया, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लबकुमार देब ने मुख्य अतिथि के रुप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में सभी को यह उपकरण वितरित किये।

केवीआईसी के प्रयासों को लागू करते हुए, मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देब ने कहा, "यह मेगा उपकरण वितरण और क्षमता निर्माण अभियान लोगों के लिए आजीविका पैदा करेगा और 700 लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। त्रिपुरा भौगोलिक रूप से पृथक राज्यों में से एक है और इसमें अनगिनत चुनौतियां हैं,

जिन पर मौजूदा सरकार काम कर रही है। हनी मिशन, चर्म कारीगर सशक्तिकरण कार्यक्रम और कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं बल्कि समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने और उन्हे समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह अधिकतम लोगों तक पहुंचने और उन्हें सम्मान दिलाने में मदद करने का एक प्रयास है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा, "प्रधानमंत्री के विजन के साथ, हमारा प्रयास आजीविका के अवसरों के साथ-साथ ग्रामीण किसानों और अन्य कारीगरों को आय का वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना है, जो अन्य सघन श्रम को अपनाते हैं या दैनिक वेतन नौकरियों के लिए शहरों और बड़े शहरों में पलायन करते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य न केवल ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाना है और उन्हें मधुमक्खीपालन, मिट्टी के बर्तनों बनाने और चर्म कार्य कलात्मकता में विश्वास दिलाने में मदद करना है, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करना है। रबड़ के पौधों की बड़े पैमाने पर खेती और उनके घरों में पारंपरिक टेराकोटा उत्पादों के उपयोग की वजह से त्रिपुरा में मधुमक्खीपालन और कुम्हारी उद्योग की काफी संभावनाएं हैं।

इस आयोजन में अगरतला के आसपास के जिलों के कारीगर की बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उपकरण वितरण के लाभार्थियों में से लगभग 20% महिलाएं थीं, और कुल लाभार्थियों में से लगभग 80% सीमांत समुदायों के थे।

आयोग ने पेपरेक्स-2019 में भाग लिया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के हाथ कागज और रेशा उद्योग निदेशालय ने प्रगति मैदान,नई दिल्ली में 14 वीं अंतर्राष्ट्रीय पेपरेक्स-2019 प्रदर्शनी में भाग लिया। यहाँ देश के विभिन्न हिस्सों से हाथ कागज इकाइयों द्वारा निर्मित हाथ कागज और हाथ कागज उत्पादों का विशेष प्रदर्शन किया गया।

पेपरेक्स-2019 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना ने 3 दिसंबर, 2019 को हाथ कागज पैविलियन का उद्घाटन किया जो इस प्रदर्शनी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की हाथ कागज पैविलियन आगंतुकों के बीच एक विशेष आकर्षण के केंद्र बनी हुई थी। प्रदर्शनी में हाथ कागज के निर्माण का जीवंत प्रदर्शन भी किया गया।

हाथ कागज एक इको फ्रेंडली उत्पाद है, जिसका उपयोग एक गैर-वन आधारित कच्चे माल के रूप में हस्तनिर्मित कागज उद्योग के लिए किया जाता है। घरेलू और निर्यात बाजार में इस उद्योग की व्यापक क्षमता एवं संभावनाएं हैं। भारत सरकार

भी आम उपयोग के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर रोक लगा रही है, जिसके सथाप पर हाथ कागज थैले का उपयोग की व्यापक संभावना है, जिससे हाथ कागज थैले के निर्माण और बिक्री में वृद्धि करने में सहयोग मिलेगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने आयोग के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और हाथ कागज इकाइयों के प्रत्येक स्टाल का दौरा किया और इकाइयों द्वारा किए गए प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने हाथ कागज उद्योग के क्षेत्र में काम कर रहे कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट को सहयोग देने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पेपरेक्स में भाग लेने के पश्चात प्रतिभागी इकाइयों को देश भर से इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यवसायियों से निर्यात आदेश प्राप्त करने में सहयोग मिलेगा।

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना, चेन्नई में 28 दिसंबर, 2019 को तीसरे खादी फ्रेंचाइज आउटलेट का उद्घाटन करते हुए।

केवीआईसी पेंशनरों के लिए पेंशन भुगतान प्रणाली को मजबूत करने हेतु आयोग और भारतीय स्टेट बैंक, सीपीपीसी की बैठक

खादी और ग्रामोद्योग आयोग और भारतीय स्टेट बैंक, सीपीपीसी के बीच एक बैठक 03.12.2019 को होटल जुहू प्लाजा, मुंबई में पेंशन संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने और केवीआईसी पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए पेंशन भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए आयोजित की गई थी।

इससे पहले, बैठक की शुरुआत वित्तीय सलाहकार के मुख्य भाषण से हुई, उन्होंने बताया कि 1956 के KVIC अधिनियम के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष या इसके प्रतिनिधि आयोग के सदस्य होंगे। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के पीछे कारण यह था कि भारत सरकार पूर्व में एसबीआई के माध्यम से केवीआईसी को ऋण स्वीकृत करता था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवीआईसी के पेंशनभोगियों की संख्या 3000 से अधिक है, जिनके एसबीआई के साथ ही उनके पेंशन खाते हैं और पेंशनरों की वर्तमान संख्या कर्मचारियों की संख्या से अधिक है। पेंशनरों को कई शिकायतें हैं और यह पहली बार है, कि पेंशन के मुद्दों के साथ-साथ खातों के रखरखाव से संबंधित प्रमुख सीपीपीसी के साथ इस तरह की बैठक बुलाई गयी है। बैठक में यह भी अनुरोध किया गया कि चूंकि केवीआईसी के पेंशनभोगी देश भर में फैले हुए हैं, क्या सभी पेंशन मामलों को संभालने के लिए एकल सीपीपीसी की व्यवस्था का पता लगाया जा सकता है।

सुश्री प्रीता वर्मा, सीईओ ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति लाभ प्रत्येक पेंशनभोगी का अधिकार है जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। उन्होंने, 7 वें वेतन आयोग से संबंधित मुद्दों और इसके

कार्यान्वयन (2.57 और मैट्रिक्स तालिका के बीच अंतर) सहित कुछ अन्य मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया। उन्होंने कहा कि संशोधित पेंशन नहीं दी जा रही है, जिसमें परिवार के पेंशनरों को संशोधित परिवार पेंशन प्राप्त नहीं होने के कारण नुकसान होता है और इसे कैसे पारदर्शी बनाया जा सकता है। इस दिशा में डिजिटल हस्तक्षेप के साथ समाधान की जरूरत है।

उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि "जब पेंशनभोगियों को पेंशन में देरी और पेंशनरों को होने वाली कठिनाई के बारे में, जब हमसे वे संपर्क करते हैं तो यह बहुत बुरा लगता है"। आयोग ने अपने पेंशनरों एसोसिएशन के लिए एक कार्यालय आवंटित किया है ताकि पेंशनरों की समस्याओं को हल करने के लिए आयोग प्रशासन के साथ चर्चा और समन्वय कर सकें। और आयोग का कर्तव्य है कि वह सभी पेंशनभोगियों के अधिकारों का समय पर संवितरण करे।

आयोग के निदेशक (प्रशासन व मा.सं.) ने पेंशन से संबंधित मुद्दों और पेंशन प्रणाली पर एक संक्षिप्त परिचयात्मक नोट प्रस्तुत किया और बताया कि लगभग 784 आयोग के शून्य बैठक के दौरान निम्नलिखित मुद्दों को हल करने के लिए ध्यान केन्द्रित किया गया:

01. 2016 से पूर्व केवीआईसी पेंशनरों का, 7 वे वेतन आयोग के अनुसार पेंशन का पुनरीक्षण।
02: केवीआईसी पेंशनरों को 2016 के बाद, 7 वे वेतन आयोग के अनुसार पेंशन का पुनरीक्षण।
03: आयोग के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को पेंशन भुगतान के लिए मोडस ऑपरेंडी।
04: केवीआईसी को पेंशनभोगी की मृत्यु की गैर सूचना और पारिवारिक पेंशन सीधे बैंक द्वारा शुरू की गई।
05: संबंधित एसबीआई सीपीपीसी को पेंशन बैंक खातों का माइग्रेशन।
06: पेंशन के लिए पेंशन भुगतान एरियर्स (LTA) और पेंशन की रिकवरी भुगतान (एमएसीपी के मामले में वापस लिए गए)
07: मृत्यु के बाद होने वाली समस्याओं का सामना करती पेंशनर्स पेंशन फाइलें
08: 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 95 वर्ष और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त क्वांटम का भुगतान न करना।
09: (ए) अखिल भारतीय पेंशनर्स वेल्फेयर एसोसिएशन के सभी के लिए मुद्दों पर सीपीपीसी के साथ चर्चा।

आयोग द्वारा महिलाओं को विद्युत चालित कुम्हारी चाक वितरित

महिलाओं के लिए उद्यमिता के अवसरों को तलाशने हेतु, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने जनिया, बारपेटा, असम के बीपीएल परिवारों की महिला कारीगरों को विद्युत चालित कुम्हारी चाक का वितरण किया और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया।

आयोग ने डा. बी. आर. अम्बेडकर को दी श्रद्धांजलि

आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 6 दिसंबर, 2019 को संविधान के निर्माता डॉ. बी.आर अम्बेडकर की 63 वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

विविध

आयोग बेरोजगार युवाओं को उद्यमिता की ओर उन्मुख करने में एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आयोग के राज्य कार्यालय, देहरादून ने 2 दिसंबर 2019 को प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया।

आयोग के विभागीय बिक्री केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग भवन ने टाउन हॉल, एर्नाकुलम में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन कोच्चि मेयर द्वारा किया गया।

24 दिसंबर 2019 को जबलपुर में राज्य कार्यालय भोपाल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी।

पीलीभीत में 18 दिसंबर 2019 को विनोवा सेवा आश्रम, नकोदाना में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आयोजित 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद प्रशिक्षित 20 कुम्हारों को जिलाधिकारी श्री वैभव श्रीवास्तव द्वारा विद्युत चालित कुम्हारी चाक और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत नि: शुल्क विद्युत चालित कुम्हारी चाक के साथ ही 90 प्रतिशत अनुदान पर 10 कुम्हारों के समूहों को एक क्लीवेज ब्लैंजर मशीन प्रदान की गयी।

कार्यक्रम के दौरान, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री अतुल सिंह, आयोग के राज्य कार्यालय, लखनऊ के सहायक निदेशक श्री ए.के. मिश्रा, खादी बोर्ड के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बिनोवा सेवा आश्रम के सचिव और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

27 दिसंबर को हनी मिशन कार्यक्रम के तहत
नासिक जिले में मधुमक्खी
बक्सों का वितरण

प्रेस कवरेज

Millennium Post, Delhi
Wednesday, 18th December 2019; Page: 2
Width: 24.85 cms; Height: 39.63 cms; a3; ID: 2.2019-12-18.17

Gadkari launches sale of *Khadi Rumal*

Union Minister for Micro, Small and Medium Enterprises Nitin Gadkari, on December 17, launched the sale of Khadi Rumal, in the presence of VK Saxena, Chairman, Khadi and Village Industries Commission (KVIC) and Secretary MSME Arun Panda.

Struggling to sustain their existence, families of militancy affected areas of Kashmir shifted to Nagrota a few years back. In 2016, KVIC started a napkin stitching center in Nagrota for the women impacted by the lack of livelihood opportunities and unemployment, to help them become self-dependent and sustain their families.

Speaking about the initiative, Nitin Gadkari said, "This initiative of KVIC is the true reflection of Bapu's vision of empowering the weakest of the society, and an appeal to the people to support this unique initiative which is creating jobs for needy."

Chairman, KVIC, Shri VK Saxena said, "This 'Khadi Rumal' is not just a piece of cloth, but a symbol of trust that the women in militancy affected areas residing in Nagrota, have on the people of India to enable them and empower them to live a life of dignity and respect. The sale of this 'Khadi Rumal' will instill confidence and enable the women all over Kashmir to come out and stand for themselves, earn a respectful livelihood and take care of their families. Its time for India to unite and help the cause."

White Khadi Rumal, made of pure cotton, will be sold across various Khadi outlets in India. To increase the outreach and availability of these Rumals through digital platform, KVIC has also signed an agreement with Paytm, which has committed to sell 2 Crore packets of Khadi Rumal through its online/offline platforms and mobile application.

Saxena further said, "We have targeted to sell 5 Crore pieces of Khadi Rumal initially. To create 5 Crore pieces of Khadi Rumal, around 15 Lakh Kgs of cotton will be consumed, and it will require 25 lakh man-days of spinning, 12.5 lakh man-days of weaving and around 7.5 lakh man-days required for cutting, stitching and packing of Khadi Rumal. Thus creating 44 lakh man-days of livelihood yielding wages amounting to Rs 88 Crores for various artisans. A humble contribution of the citizens of India could be a stepping stone for the beginning of the 'Journey of Transformation'."

PM Modi has already appealed the people to buy at least one Khadi Rumal.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Line, Delhi
Wednesday, 18th December 2019; Page: 15
Width: 17.27 cms; Height: 14.31 cms; a4; ID: 34.2019-12-18.102

Gadkari launches 'Khadi Rumal' made by militancy-affected women of J&K

'If people get jobs in rural areas, then they will not have to go elsewhere'

Nitin Gadkari, MSME Minister

OUR BUREAU
New Delhi, November 17

In a bid to create employment opportunities for the women from militancy-affected families of Jammu and Kashmir, the Minister for Micro, Small and Medium Enterprises Nitin Gadkari launched the sale of *Khadi Rumal* stitched by the women of Nagrota town in J&K.

"Our aim is to provide employment to the women in the terrorist-affected areas," said Gadkari. If people living in rural areas are provided job opportunities then they would not need leave their homes in search of jobs, he added. At the event on Tuesday, Gadkari also announced a 50 per cent increase in remuneration of women workers to ₹3 per piece from ₹2 now.

Turnover

The turnover of the village industries in the country is ₹75,000 crore and by March 2020, the aim is to increase this turnover to ₹100,000 crore, Gadkari added.

Khadi and Village Industries Commission (KVIC) also signed an agreement with Paytm to facilitate the sale of 2 crore pieces of *rumals* through their portal.

A *Rumal* costs ₹50 and, in the initial phase, the plan is to produce five crore pieces.

Home minister pushes para-military forces to use khadi in their uniforms

By Mail Today Bureau
New Delhi

"It is noteworthy that the sample developed by KVIC for the camouflage uniform fabric was not only liked by one of the para-military forces but was also found quite superior from the existing material used by the forces."

VINAI KUMAR SAXENA
Chairman, Khadi and Village Industries Commission (KVIC)

Union Home Minister Amit Shah recently instructed the director generals of all para-military forces to use khadi fabric in their uniforms and village industries' products in their canteens.

SHORT TAKES

Gadkari launches 'Khadi Rumal' made by militancy-affected women of J&K

'If people get jobs in rural areas, then they will not have to go elsewhere'

Nitin Gadkari, MSME Minister

OUR BUREAU
New Delhi, November 17

In a bid to create employment opportunities for the women from militancy-affected families of Jammu and Kashmir, the Minister for Micro, Small and Medium Enterprises Nitin Gadkari launched the sale of *Khadi Rumal* stitched by the women of Nagrota town in J&K.

"Our aim is to provide employment to the women in the terrorist-affected areas," said Gadkari. If people living in rural areas are provided job opportunities then they would not need leave their homes in search of jobs, he added. At the event on Tuesday, Gadkari also announced a 50 per cent increase in remuneration of women workers to ₹3 per piece from ₹2 now.

Turnover

The turnover of the village industries in the country is ₹75,000 crore and by March 2020, the aim is to increase this turnover to ₹100,000 crore, Gadkari added.

Khadi and Village Industries Commission (KVIC) also signed an agreement with Paytm to facilitate the sale of 2 crore pieces of rumals through their portal.

A Rumal costs ₹50 and, in the initial phase, the plan is to produce five crore pieces.

प्रेस कवरेज

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi
Wednesday, 18th December 2019; Page: 11
Width: 16.24 cms; Height: 17.86 cms; a4; ID: 28.2019-12-18.84

खादी ग्रामोद्योग दो लाख करोड़ का होगा : गडकरी

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

सड़क परिवहन व सूक्ष्म, लघु-मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग का करोबार अगले पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है।

ग्रामोद्योग से ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे आंतकवाद, उग्रवाद व नक्सलवाद व अन्य कारणों से शहरों की ओर पलायन करने वालों को रोका जा सकेगा। गडकरी ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के एक रुमाल हजारों धागे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इन रुमालों को जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित महिलाओं द्वारा तैयार किया गया है। केवीआईसी ने जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहीं इन महिलाओं को 2016 में खादी रुमालों को तैयार करने का काम दिया था। अभी तक पांच करोड़ रुमाल तैयार किए जा चुके हैं।

DC Reasi distributes electric-potters wheels

GK NEWS NETWORK

Reasi, Dec 6: Deputy Commissioner Reasi Indu Kanwal Chib and State Director Khadi Village Industries Commission (KVIC) DS Bhati on Friday handed over electric potters-wheels to the 20 beneficiaries on highly subsidised rates and after due training by KVIC at district headquarters here.

Speaking on the occasion, the DC said that it will provide a self employment to the potters and will also help us to phase out hazardous single-use-plastic from the district.

The State Director, DS Bhati, said that the beneficiaries have also been provided a 10-day hands-on training on the machine. He further said that KVIC is going to organize a number of employment generation awareness camps under Honey Mission, Cobblers Mission and PMEGP in J&K.

in the meeting.

DC Reasi distributes electric-potters wheels

ROHIT SHARMA

REASI, DEC 6: Deputy Commissioner Reasi Indu Kanwal Chib and State Director Khadi Village Industries Commission (KVIC) DS Bhati today handed over electric potters-wheels to the 20 beneficiaries on highly subsidised rates and after due training by KVIC at district headquarters here today.

Speaking on the occasion, the DC said that it will provide a self employment to the potters and will also help us to phase out hazardous single-use-plastic from the district.

The State Director, DS Bhati, said that the beneficiaries have also been provided a 10-day hands-on training on the machine. He further said that KVIC is going to organize a number of employment generation awareness camps under Honey Mission, Cobblers Mission and PMEGP in J&K.

MADE-IN-INDIA SHIFT

Over 1 m Paramilitary Men to Don Khadi Uniform, Combat Outfit

Decision on attire change comes after prod from home minister Amit Shah

Anubhuti Vishnoi & Rahul Tripathi

New Delhi: India's paramilitary forces will soon be seen in uniforms made of handwoven fabric, or Khadi. The decision was taken by home minister Amit Shah, people aware of the development told ET.

Shah is learnt to have asked heads of all central forces to switch to 'Make in India' products and promote use of khadi, including using Khadi fabric for uniforms.

Home ministry officials confirmed the development saying that more than 1 million personnel of CRPF, BSF, SSB, ITBP, CISF, NSG and Assam Rifles will be using uniform made of terry-Khadi. These forces currently use cotton and terry-cotton, among other fabrics, for uniforms, depending upon their durability.

The central forces are in advanced discussions with Khadi and Village Industries Commission (KVIC) to procure raw material and the latter has shared samples of cotton and woollen uniforms, camouflage uniforms as well as blankets for the para-military forces. All these are likely to get final approval in the next few days, the officials said.

"The central forces have their specifications for the uniform. We have asked Khadi Commission to provide fabric as per our requirements," a senior home ministry official said. "Forces like ITBP and BSF may have different requirements than CRPF and SSB. It is important to mention here that the soldiers deployed in border areas or on patrol are required to carry weapons and arms for which the requirements are different."

Prime Minister Narendra Modi has been advocating the use of Khadi and has termed it a "movement" to be adopted on mission mode. While several government institutions have begun using Khadi in response, this will probably mark the biggest such shift towards Khadi in the country.

It is estimated that each paramilitary force will place an order worth ₹150-200 crore with KVIC.

The BSF (Border Security Force) alone is learnt to have sought 1.1 million metres of Khadi fabric for readying the uniforms of its personnel.

"This move will not only double the Khadi and Village Industries' turnover, which is nearly ₹75,000 crore currently, but also create millions of additional man hours for the Khadi artisans, who will weave millions of metres of Khadi fabric for our paramilitary forces," KVIC chairman, Vinai Kumar Saxena, told ET.

The home ministry is also learnt to have asked the paramilitary canteens to preferably stock up on Khadi products like pickles, papad, honey, soaps and detergents, shampoos, phenol, tea, mustard oil, etc.

"As the home minister has also asked the forces to keep different village industries' products in all their canteens, it will certainly create faith and confidence among the artisans, as their niche products will now be showcased before the real guards of our nation," Saxena said. "Hon'ble home minister's instruction reflects Prime Minister Narendra Modi led government's vision and commitment for the makeover of this signature fabric of nation."

25 ACRES INDUSTRIAL
NEAR HARIDWAR
FOR SALE
• Cheapest power in North India
• Availability of plenty of ground w
• Highly conducive industrial Envi

AGARWAL PACKERS AND MOVERS LTD.
LOOK Before BOOK
FOUNDER'S PHOTO WITH CAP
09 300 300 300

प्रेस कवरेज

दैनिक भास्कर

आमला . भैंसदेही. घोड़ाडोंगरी. शाहपुर . चि

आय बढ़ाने की कवायद • 10 दिनों का होगा प्रशिक्षण, विभिन्न प्रांतों के चुनिंदा कारीगर होंगे शा

शाहपुर में मिट्टी की कारीगरी सीख रहे महाराष्ट्र, गुजरात व यूपी के कलाकार

पतौवापुरा में पहली बार होगा कलाकारों की आय बढ़ाए जाने की पहल

भजन सिंह ठाकुर | शाहपुर

[illegible]

शाहपुर। आधुनिक मशीन से मिट्टी के बर्तन बनाने की कला सीखते हुए कलाकार।

प्रशिक्षण लेने वाले कलाकार

[illegible]

ये बनाना सीखेंगे कलाकार

[illegible]

ये हुई पहल- जुटे अन्य प्र... के कलाकार, प्रयोग सफ... रहा तो आगे भी देंगे प्रशि...

[illegible]

जिलाधिकारी ने 20 कुम्हारों को बांटे इलेक्ट्रॉनिक चाक और प्रमाण-पत्र

पीलीभीत | हिन्दुस्तान संवाद

डीएम वैभव श्रीवास्तव ने बुधवार को 20 कुम्हारों को इलैक्ट्रानिक चाक और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया। डीएम के हाथों सम्मान पाकर कुम्हारों के चेहरे खिल उठे। नकटादाना चौराहे के पास स्थित बिनोवा सेवा आश्रम में कुम्हारों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतिम दिन डीएम पहुंचे और किसानों को सम्मानित किया।

खादी ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) की ओर से कुम्हारों को सशक्तिकरण के लिए 10 दिसवीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 20 कुम्हारों को विद्युत चाक का प्रशिक्षण दिया गया। युवा समाज सेवा जन कल्याण जन कल्याण सेवा समिति के प्रशिक्षक वेदपाल ने कुम्हारों को प्रशिक्षण दिया। समापन पर डीएम वैभव श्रीवास्तव ने कुम्हारों से कहा कि विद्युत चाक उपलब्ध होने से आप सभी को वर्षा और खराब मौसम की वजह से कार्य में बाधा नहीं आयेगी। मिट्टी के लिए कहीं कोई दिक्कत आती है तो वह बताए। इस दौरान कुम्हारों ने कुछ समस्या भी उठाई। कार्यक्रम में आए खादी ग्रामोद्योग आयोग लखनऊ के सहायक निदेशक एके मिश्रा ने बताया कि बुधवार को 20 कुम्हारों को विद्युत चाक दी गई। प्रत्येक की कीमत 19 हजार 500 है। इसमें 90 प्रतिशत कुम्हारों को अनुदान है। यानी कुम्हारों से मात्र एक मशीन के एवज में 1950 रुपये लिए गए। इसके अलावा कुम्हारों के दो समूहों को क्लेब ब्लजंर मशीनें दी गई है। उन्होंने बताया इससे पहले 40 कुम्हारों को मशीनें दी जा चुकी हैं। इस मौके पर सीडीओ आरसी पांडेय, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एके गंगवार आदि अधिकारी मौजूद रहे।

कुम्हारों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे डीएम वैभव श्रीवास्तव। • हिन्दुस्तान

डीएम ने लिया जायजा : समापन कार्यक्रम में पहुंचे डीएम ने सभी प्रकार की सामग्री का अवलोकन करते हुए सराहना की। कुम्हारों को प्रेरित करते हुए कहा कि कुम्हारी कला हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है और मिट्टी के बर्तनों में खाने योग्य बनी सामग्री वैज्ञानिक रूप से भी अति स्वादिष्ट होती है।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक बोले

'बेरोजगारी से मुक्ति का कारगर साधन है खादी'

ग्राम हाथनौदा में रोजगार जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते वक्ता।

रोजगार जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

चौमूं. खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक बद्रीलाल मीना ने कहा कि बेरोजगारी से मुक्ति पाने का सबसे कारगर साधन खादी है। उन्होंने युवाओं से खादी से जुड़ने का आह्वान किया। मीना रविवार को ग्राम हाथनौदा स्थित अंबेडकर विकास समिति की ओर से संचालित खादी एवं ग्रामोद्योग कताई-बुनाई उत्पत्ति केंद्र में आयोजित रोजगार जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण व प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आयोग इस साल 108 करोड़ रुपए की राशि स्वरोजगार करने वालों को बांटेगा। इससे लाभार्थी अपना रोजगार शुरू कर सकता है। इस ऋण पर सब्सिडी भी है।

मीणा ने बताया कि शहद उत्पादन के लिए ऋण व प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेह व लद्दाख में जो शहद बनाया जा रहा है वो 7 हजार रुपए किलो बिक रहा है। राजस्थान के युवा चाहें तो ऐसी स्थिति अपने यहां भी हो सकती है। उन्होंने आयोग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधानाध्यापक अर्जुन लाल बलाई ने की। अंबेडकर विकास समिति के मंत्री रामजीलाल वर्मा ने कहा कि संस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्था के माध्यम से करीब 500 परिवारों की आजीविका चल रही है। समिति के अध्यक्ष मोहनलाल वर्मा ने कहा कि युवाओं को ऐसी योजनाओं से जुड़कर लाभ उठाना चाहिए। हाथनौदा सरपंच कैलाश सैनी ने भी विचार व्यक्त किए। मंच संचालन डॉ संगीता वर्मा ने किया। इस दौरान गंगाराम वर्मा, कविता वर्मा, ओमप्रकाश नारनोलिया, सोहनलाल वर्मा, घनश्याम वर्मा, हंसराज नारनोलिया, कृष्णा नारनोलिया, सुशील वर्मा आदि उपस्थित थे। (का.सं.)

10 लाख जवान पहनेंगे खादी से तैयार वर्दी

NBT

■ ईटी, नई दिल्ली

अर्धसैनिक बलों के 10 लाख जवान हाथ से बुने हुए कपड़े या खादी से तैयारी वर्दी पहनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये फैसला लिया है। बताया जाता है कि शाह ने सभी पैरा मिलिट्री बलों के प्रमुखों से इसकी संभावना तलाशने को कहा है कि मेक इन इंडिया अभियान के तहत खादी को प्रोत्साहन देने के लिए जवानों की वर्दी में इसका प्रयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एनएसजी और असम राइफल्स के 10 लाख जवानों को टेरी-खादी से तैयार वर्दी दी जाएगी। फिलहाल ये जवान कॉटन और टेरी-कॉटन से तैयार वर्दी पहनते हैं। इससे तैयार वर्दी जल्दी खराब नहीं होती।

सूत्रों के मुताबिक इस बाबत केंद्रीय बलों की खादी एवं ग्रामोद्योग उद्योग आयोग (केवीआईसी) से बातचीत चल रही है। आयोग की तरफ से बलों को जांच परख के लिए कुछ सैंपल भी भेजे गए हैं। अंतिम रूप देने के बाद वर्दी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

> गृह मंत्री अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों को दिया लक्ष्य

बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार खादी का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं और उन्होंने इसे आंदोलन का रूप देने की वकालत की है। तमाम सरकारी संस्थानों में खादी के प्रयोग को बढ़ावा मिला है और अर्धसैनिक बलों से खादी को जोड़ने को अब तक का सबसे बड़ा अभियान माना जा रहा है।

प्रेस कवरेज

कर दी गई है। तहसीलदार विजय कुमार त्रिवेदी ने सभी लेखपालों से हड़ताल समाप्त कर कार्य पर लौटने की अपील

अन्य लेखपालों पर सर्विस ब्रेक की कार्रवाई की गई है।

बीस कुम्हारों को प्रदान किए विद्युत चालित चाक

वितरण

- डीएम ने मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा देने की बताई जरूरत
- कुम्हारी कला देश की प्राचीन संस्कृति का हिस्सा रही है

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने दस दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बीस कुम्हारों को विद्युत चालित चाक प्रदान किए। उन्होंने कहा कि कुम्हारी कला इस देश की प्राचीन संस्कृति का हिस्सा रही है। उन्होंने कुम्हारी कला को बढ़ावा दिए जाने पर जोर देते हुए कहा कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए , जिससे कुम्हारी कला का कार्य करने वालों की आमदनी बढ़ सके।

'बुधवार को नकटादाना चौराहा के निकट स्थित विनोबा सेवा आश्रम में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीएम ने कहा कि विद्युत चालित चाक वितरण के साथ ही दस कुम्हारों के समूह को क्लेब ब्लंजर यंत्र भी निशुल्क दिया जा रहा है। इस यंत्र के माध्यम से उनके लिए मिट्टी को गूंथना आसान हो जाएगा। कुम्हार इससे अधिक से अधिक सामग्री निर्मित कर सकेंगे। हर मौसम में वे कारोबार जारी रख सकेंगे। डीएम ने कहा कि इससे पहले प्रशिक्षण पाने वाले 40 कुम्हारों को विद्युत चालित प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कुम्हारी कला को बढ़ावा देने के लिए यह योजना चलाई है। डीएम ने विद्युत चालित चाक पर बनाई गई वस्तुओं का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि कुम्हारों की सभी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। एडीएम अतुल सिंह, सीडीओ रमेश चंद्र पांडेय, खादी एवं ग्रामोद्योग के सहायक निदेशक एके मिश्र समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

2 लाख 52 हजार 337 बच्चों को किया गया चिह्नित

चा खुराक पीने से वंचित न रहे

कार्यशाला का हुआ आयोजन

'खादी के आयाम हैं पर्यावरण के दोस्त'

प्रधानमंत्री रोजगार के अन्तर्गत प्रदेश को मिले 108 करोड़ रुपए

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

फागी. खादी के विभिन्न प्रकार के आयाम पर्यावरण के दोस्त हैं। खादी उत्पादन का ग्रामीण क्षेत्र है। कस्बे में जन शिक्षण संस्थान में खादी एवं ग्रामद्योग पर आयोजित कार्यशाला में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के राज्य निदेशक बद्रीलाल मीना ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि दो गाय या भैंस वाले किसानों को बायोगैस प्लांट लगाने के लिए 12 हजार रुपए की छूट मिलेगी।

प्रधानमंत्री रोजगार के अन्तर्गत प्रदेश को 108 करोड़ रुपए मिले हैं। इस राशि का 40 प्रतिशत हिस्सा जिला उद्योग केन्द्र को दिया गया है। 20 प्रतिशत शहर के तथा 20 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए दिया जाना है। राजस्थान खादी बोर्ड को 30 प्रतिशत पैसा रोजगार के लिए दिया गया है।

इस स्कीम के तहत सिलाई, टैंट, ढाबा अन्य रोजगार के लिए 10 लाख रुपए आवंटित किए जाते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रेडिमेड गारमेंट, दूध के प्रोडेक्ट, खेतों की मेड़ के लिए खंभे बनाने के लिए 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इसमें सभी आवेदन कर सकते हैं। कुम्हारों के लिए 5 हजार इलेक्ट्रिक चाक बीपीएल को निःशुल्क, एपीएल श्रेणी के लोगों को 1915 रुपए में वितरित करने का लक्ष्य है। मोची का कार्य करने वाले कथित चर्म चिकित्सक के औजारों का तीन हजार रुपए की कीमत के टूल किट निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं।

विभाग ने हनी मिशन शुरू किया है। मधुमक्खी पालन के एक बक्से की 3648 रुपए कीमत है जबकि एससी एसटी के लोगों को 3648 रुपए तथा जनरल को 7हजार 200 रुपए में 10-10 बक्से दिये जा रहे हैं। जिसके जरिए बेरोजगार उद्योग लगाकर लाभ उठा सकते हैं। राज्य निदेशक मीना ने स्थानीय जन शिक्षण संस्थान में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की योजनओं का ग्रामीणों को लाभ दिलाने के लिए स्वीकृति दी है। कार्यक्रम में संस्था के संचालक अमित कुमावत, पू सरंपच सीताराम पारीक जीएसएस अध्यक्ष ओम प्रकाश खवास सहित ग्रामीण उपस्थित थे।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पेपरेक्स प्रदर्शनी में भाग लिया

मुंबइ। हाथ कागज और फाइबर उद्योग निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित 14वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पेपरेक्स 2019 में भाग लिया है। यहाँ देश के विभिन्न हिस्सों से हाथ कागज कागज इकाइयों द्वारा निर्मित हाथ कागज और उत्पादों का विशेष प्रदर्शन किया गया है। पेपरेक्स 2019 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने 3 दिसंबर 2019 को हाथ कागज पैविलियन का उद्घाटन किया जो इस प्रदर्शनी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग का हाथ कागज पैविलियन आगंतुकों के बीच एक विशेष आकर्षण के केंद्र बना हुआ है । प्रदर्शनी में हाथ कागज के निर्माण का जीवंत प्रदर्शन भी किया गया है। हाथ कागज एक इको फ्रैंडली उत्पाद है, जिसका उपयोग एक गैर-वन आधारित कच्चे माल के रूप में हस्तनिर्मित कागज उद्योग के लिए किया जाता है। घरेलू और निर्यात बाजार में इस उद्योग की व्यापक क्षमता एवं संभावनाएं हैं।

भारत सरकार भी आम उपयोग के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग करने जा रही है जिसमें हाथ कागज थैले का उपयोग करने की संभावना है, जिससे हाथ कागज थैले के निर्माण और बिक्री में वृद्धी में सहयोग मिलेगा।

स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनें युवा

- जागरुकता शिविर आयोजित कर युवाओं को दी जानकारी

भास्कर समाचार सेवा

बागेश्वर। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत एक दिवसीय जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर खादी एवं ग्रामोद्योग के सहायक निदेशक बीएस कंडारी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। गरुड़ में आयोजित शिविर में जानकारी देते हुए कंडारी ने कहा कि उनका विभाग प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत छोटे-छोटे उद्योगों के लिए सहायता मुहैया करा रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ के युवक व युवतियों को 35 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। ताकि पहाड़ से पलायन भी रुक सके। आयोग के सहायक निदेशक द्वितीय जेएस मलिक ने इस योजना के ऑनलाइन आवेदन की तकनीकी जानकारी दी। जिला समन्वयक हरीश चंद्र ने कहा कि किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर युवा उनसे संपर्क करें। देहरादून से आए सलाहकार शैलेश रावत ने भी युवाओं को जानकारी दी। इस दौरान समाजसेवी सदन मिश्रा, गिरीश बिष्ट, मेलाडुंगरी के ग्राम प्रधान बलवंत भंडारी, राजेंद्र गोस्वामी, राजेंद्र ऐठानी समेत दर्जनों युवक-युवतियां मौजूद थे।

खादी का कारोबार अगले पांच साल में दो लाख करोड़ रुपए

नयी दिल्ली। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नीतिन गडकरी ने खादी एवं ग्रामोद्योग का कारोबार अगले पांच साल में दो लाख करोड़ रुपए करने का आह्वान करते हुए मंगलवार को कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और आतंकवाद, उग्रवाद तथा नक्सलवाद के अलावा शहरों की ओर लोगों का पलायन रोका जा सकेगा। श्री गडकरी ने यहां खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम 'एक रुमाल हजारों धागे' को संबोधित करते हुए कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग का मौजूदा कारोबार 75 हजार करोड़ रुपए का है। इसे अगले वर्ष के अंत तक एक लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना खादी और ग्रामोद्योग के कारोबार को अगले पांच साल में दो लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने की योजना बनाई है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का प्रयास कर रही है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर कई योजनायें चलायी जा रही हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से गरीबों और वंचितों को सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यस्था मजबूत करने के ऐसे कार्यक्रमों के जरिए आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद और पलायन जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता है।

श्री गडकरी ने कहा कि 'एक रुमाल हजारों धागें' कार्यक्रम से लाखों ग्रामीण परिवारों का जीवन जुड़ा है। जम्मू कश्मीर के नगरोता में आतंकवाद से प्रभावित महिलायें ये रुमाल बना रही है। ये रुमाल गुणवत्ता में बेहतर हैं और बाजार में उपलब्ध अन्य रुमालों से सस्ते हैं। प्रत्येक रुमाल की कीमत 50 रुपए है और इनमें दो रुपए महिला कारीगर को मिलते हैं। ये रुमाल हाथ से बने धागे और कपड़े से निर्मित किये जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने महिला कारीगरों को तीन रुपए प्रति रुमाल देने की घोषणा भी की।

प्रेस कवरेज

पुणे जिल्हा
प्रभात पुणे, रविवार, दि. १५ डिसेंबर २०१९
३

राज्यातील १५०० कुंभारांना आधुनिक प्रशिक्षण

पुणे जिल्ह्यातही खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे कुंभार सशक्तीकरण मिशन : १४० कारागिरांना प्रमाणपत्र

बारामती, दि. १४ (प्रतिनिधी) - कुंभार सशक्तीकरण मिशन अंतर्गत आतापर्यंत दोन वर्षांमध्ये देशामध्ये १५ हजार व राज्यामध्ये १५०० कुंभार कारागिरांना यांत्रिक चाके व इतर मशीनचे वाटप करण्यात आलेले आहे. यानुसार खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार यांच्या कुंभार सशक्तीकरण मिशन अंतर्गत व इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन यांच्या विशेष फंडातून पुणे जिल्ह्यातील कुंभार काम करणाऱ्या १४० कारागिरांना कुंभार कामाचे आधुनिक प्रशिक्षण देऊन प्रमाणपत्र देण्यात आले.

अखिल महाराष्ट्र कुंभार समाज विकास संस्थेच्या सहयोगाने शहरातील डेंगळे गार्डन येथे मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला. यावेळी मुख्य महाप्रबंधक इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन मुख्य प्रबंधक श्रीधर भागवत, महा प्रबंधक अनिल लिमये, खादी ग्रामोद्योग आयोगचे संचालक ए.एल.मीना, उपसंचालक राजीव खन्ना, माती कला विकास सेलचे चेअरमन दत्ता कुंभार, अशोक सोनवणे, विठ्ठलराव राऊत, मोहन जगदाळे, श्याम राजे आदी मान्यवरांसह संपूर्ण राज्यातून कुंभार समाज विकास संस्थेचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

बारामती, भोर, कामशेत, घोडेगाव, पिरंगुट व मुंढवा येथे १० दिवसांचे आधुनिक कुंभारी कलेचे प्रशिक्षण कारागिरांना देण्यात आले. विजेवर चालणारी १४० यांत्रिक चाके तसेच ५ कारागिरांना मिळून १चिखल मशागत यंत्र व १ चिखल मळणी यंत्राचे वाटप यावेळी करण्यात आले. सदर मशीन मुळे कुंभार काम करणाऱ्या कारागिरांचे उत्पादन तीन पट वाढणार असून चिखल बनविणे व इतर कामासाठी लागणारे कष्ट ही कमी होणार आहेत. उपलब्ध असणाऱ्या स्थानिक मातीपासून चांगल्या प्रकारच्या मातीच्या वस्तू बनविता येणार आहेत. याशिवाय ५ कारागिरांच्या समूह मध्ये मातीची भांडी भाजण्यासाठी एक आधुनिक भट्टीही खादी ग्रामोद्योग आयोग बांधून देणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

आणखी २००० यांत्रिक चाकांची मागणी...

अखिल महाराष्ट्र कुंभार समाज विकास संस्थेने राज्यातील इतर जिल्ह्यातील कुंभार कारागिरांना या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग आयोग मुंबई यांच्याकडे या वर्षासाठी आणखी २००० यांत्रिक चाकांची मागणी केली व तसा प्रस्ताव खादी ग्रामोद्योग आयोग मुंबई यांना देण्यात आला आहे. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन यांनाही अशा प्रकारचे आणखी प्रकल्प मंजूर करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. इतर जिल्ह्यातही अशा प्रकारचे उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

प्रभात Sun, 15 December 2019
epaper.eprabhat.net/c/46890169

दैनिक भास्कर
09-Dec-2019
Page 4

समारोह • तालेड़ा के पास श्रीयादे माता प्रजापति समाज के मंदिर परिसर में बांटे विद्युतचलित चाक

गांव आत्मनिर्भर होगा तभी देश आगे बढ़ेगा: बिरला

शॉल व कपड़ों को बनते लाइव देखा

बिरला को ज्ञापन देने वालों का तांता

सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

समाज ने जताया आभार

मधुमक्खी पालकों को न्योता

'लघु-कुटीर उद्योगों से पूरा करें बापू का सपना'

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

बूंदी. महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को तालेड़ा कस्बे में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की ओर से विद्युत चलित चॉक, बी-बॉक्स व एडवांसड लेदर टूल किट वितरण समारोह हुआ।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लघु और कुटीर उद्योग के माध्यम से गांवों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाकर महात्मा गांधी का सपना साकार करें। आने वाले समय में चीनी का विकल्प शहद बनेगा। किसान भी श्वेत क्रांति के साथ शहद क्रांति की ओर बढ़ें। बिरला ने मधुमक्खी पालक किसानों को 500 बी बॉक्स, कुंभकार सशक्तीकरण के तहत 500 इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील तथा 200 एडवांस्ड लेदर टूल किट वितरित किए। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए जन आंदोलन की जरूरत बताई। समारोह में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना, बूंदी विधायक अशोक डोगरा, आयोग के उत्तरी क्षेत्र के अधिकारी सत्यनारायण शुक्ला, खादी ग्रामोद्योग के निदेशक बद्रीलाल मीणा, कुंभकार समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नंदलाल प्रजापति, श्रीयादे प्रजापति मंदिर के अध्यक्ष हेमराज प्रजापति ने भी विचार व्यक्त किए।

खदानों के लिए बैठक बुलाने के दिए निर्देश

रामगंजमंडी (कोटा). लाइम स्टोन की बंद खदानें वापस शुरू कराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य के वन विभाग के अधिकारियों को एक टेबल पर बैठाकर सिन्सेटिव जोन के शून्य किलोमीटर तय कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए केन्द्रीय वन सचिव को शीघ्र बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। केन्द्रीय सचिव के एक-दो दिन में विदेश दौर से लौटने के बाद यह बैठक होगी। पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलने से बंद पड़ी रामगंजमंडी क्षेत्र की डेढ़ दर्जन खदानों को शुरू कराने के लिए बिरला से आग्रह किया गया था।

पर्यावरणानुकुल उत्पादों का एक स्थान

बहुमुखी एवं मनमोहक
खादी डिजाइनर परिधानों
जैसे पर्यावरणानुकूल उत्पादों का एक स्थान
खादी वस्त्र, हर्बल उत्पाद,
रसायन रहित अगरबत्तियां,
विषाणु रहित एवं एन्टी फंगल शहद,
नैसर्गिक एवं आयुर्वेदिक सौन्दर्य उत्पाद
जैसे साबुन एवं शैम्पू,
हाथ कागज एवं पारंपरिक हस्तशिल्प
तथा अन्य उत्पादों की विशाल श्रृंखला

कामये दुरवतापानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय,भारत सरकार
ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड़, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 056.
वेबसाईट : www.kvic.org.in

Khadi India

"भारत में हम रोजगार सृजन करते है तथा समृध्दि बुनतें हैं"